

# आरक्षण बनाम डॉक्टर्सिटी

खण्ड-2



डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

आरक्षण  
बनाम  
डाईवर्सिटी

डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

दुसाध प्रकाशन  
लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2008

द्वितीय संस्करण : 2011

तृतीय संस्करण : 2020

ISBN : 978-81-87618-28-7

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए

द्वारा

प्रकाशक : दुसाध प्रकाशन

डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,  
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022  
E-mail : hl.dusadh@gmail.com  
मो. : 9654816191

प्रशासनिक कार्यालय

बी-1, 149/9 किशन गढ़, वसंत कुंज,  
नई दिल्ली-110070  
संपर्क : 011-26125979, 9654816191

© लेखक

मूल्य : 70 रुपये

रचना : आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी

रचनाकार : डॉ. विजय कुमार त्रिचरण

आवरण : शशिकान्त

शब्दांकन : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32

मुद्रक : किंवदं ऑफसेट, दिल्ली-94

## समर्पण

एच.एल.दुसाध, बुद्धशरण हंस, चन्द्रभान प्रसाद

एवं

भारत में डाइवर्सिटी आन्दोलन के उन सभी

सूत्रधारों एवं सूरमाओं

के प्रति,

जिन्होंने आर्थिक गैर-बराबरी

समाप्त करने की

भीम-प्रतीज्ञा ले रखी है।



## प्राक्कथन : प्रथम संस्करण

आंबेडकरी आन्दोलन में जो थोड़े से युवा चिंतक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, डॉ० विजय कुमार त्रिशरण उनमें से एक हैं। आप झारखण्ड के एक पिछड़े इलाके में आन्दोलन की जो अलख जगा रहे हैं, महानगरों के एक्टिविस्टों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। एक बलिष्ठ समाज विज्ञानी की भूमिका में अवतीर्ण, शल्य चिकित्सक डॉ०. त्रिशरण का सारा ध्यान-ज्ञान दलित बहुजन समाज है। इसकी मुक्ति के लिए वह बहुआयामी अभियान चला रहे हैं। एक तरफ जहां वे ब्राह्मणवाद के कारण दैविक गुलाम बने बहुजनों को आत्मा-परमात्मा, पुनर्जन्मवाद इत्यादि कुसंस्कारों से मुक्त करने के लिए बुद्धिज्ञ का प्रचार-प्रसार चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिन्दुओं द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ समाज को कमर कसने के लिए प्रेरित करने का विरल कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ वैकल्पिक आन्दोलन चलाने वाले डॉ०. त्रिशरण की सर्वोच्च प्राथमिकता में बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति एवं राष्ट्र की समृद्धि है और इसके लिए उन्हें सर्वोत्तम उपाय डाइवर्सिटी सिद्धांत लागू करवाने में ही नजर आ रहा है, इसी का दृष्टान्त है उनकी यह किताब।

इसमें कोई शक नहीं कि दलित बौद्धिक दुनियाँ में आज डाइवर्सिटी आर्थिक मुक्ति और देश में सदियों से व्याप्त आर्थिक-गैर बराबरी के खाते के सर्वोत्तम औजार के रूप में मान्यता पा चुकी है। डॉ०. त्रिशरण ने दलित बहुजन के हित में इसकी उपयोगिता साबित करने का विरल प्रयास अपनी लेखनी के द्वारा किया है। इस क्रम में वे डाइवर्सिटी की प्रयोगशाला अमेरिका की यात्रा करते हैं जहां नस्ल आधारित सामाजिक विविधता का प्रतिबिम्बन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में होता है। भारत की भाँति अमेरिका भी विविधतामय देश है। भारत में सामाजिक विविधता का मुख्य आधार जाति और धर्म है। जाति और धर्म के आधार पर यहां के लोग चार सामाजिक समूहों सर्वण, ओबीसी, एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक में बंटे हैं। लेकिन भारत के विपरित अमेरिका की सामाजिक विविधता शरीर के रंग (नस्ल) पर आधारित है। नस्ल के आधार पर वहां सबसे बड़ा सामाजिक समूहों गोरों का है जिनकी संख्या

70 प्रतिशत हैं। यही समाज वहां शासक वर्ग है जिसका संपदा संसाधनों पर वर्षे से एकाधिकार रहा है। गोरों के अतिरिक्त बाकी वंचित सामाजिक समूह अश्वेतों के हैं। वंचित नस्लीय समूहों में हैं अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस; काले (नीग्रो अथवा अफ्रीकन-अमेरिकन) जो अफ्रीकी मूल के हैं और जिन्हें सत्रहवीं सदी में अफ्रीका के जंगल से पकड़ कर लाया गया था, हिस्पेनिक्स या लैटिन मूल के लोग। इन वंचित नस्लों में कालों और रेड इंडियंस की स्थिति क्रमशः भारत के अस्पृश्य और आदिवासियों जैसी है। भारत में वंचितों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व (आरक्षण) सुलभ कराने के लिए जैसे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया वैसा अमेरिका में नहीं किया गया। वहाँ प्रतिनिधित्व का आधार बनी सामाजिक विविधता अर्थात् विभिन्न नस्लीय सामाजिक समूहों का संख्यानुपात। भागीदारी के लिए अमीरी-गरीबी कोई आधार नहीं, सिर्फ अलग-अलग सामाजिक समूहों का संख्यानुपात। मतलब जिस सामाजिक समूह की जितनी संख्या है उस अनुपात में उसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। वैसे में अमेरिका में आर्थिक गैरबराबरी मिटाने के इरादे से शुरू हुई डाइवर्सिटी (विविधता) नीति का अर्थ यह हो गया कि उनका अनुपात अमेरिका में विभिन्न नस्लीय/जातीय समूह अमेरिका में वास करते हैं, उनका वह अनुपात अमेरिका की निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों, सप्लाई, डीलरशीप, थेकों, फिल्म, मीडिया इत्यादि सहित समस्त आर्थिक गतिविधियों में दिखना चाहिए। यानी उपरोक्त आर्थिक गतिविधियों में यदि सौ-सौ लोग संलग्न हैं तो उनमें हर हाल में 28 व्यक्ति रेड इंडियंस, कालों और हिस्पेनिक्स सामाजिक समूहों से नजर आना चाहिए। इस नीति के तहत ही अमेरिका के वंचित समूहों को उनकी संख्या के हिसाब से हर क्षेत्र में अवसर मिलने की शुरूआत हुई।

लेकिन संख्यानुमात में डाइवर्सिटी के तहत अवसर मिलने की प्रक्रिया अनायास शुरू नहीं हुई। यह नीति लम्बे खुनी संघर्षों के बाद अस्तित्व में आई। खुनी नस्लीय दंगों के बाद कर्नर आयोग की सिफारिश का सम्मान करत हुये अमेरिका राज्य ने डाइवर्सिटी नीति कैसे लागू किया, कैसे राष्ट्रपति जॉनसन के जमाने में शुरू हुई इस नीति को राष्ट्रपति निक्सन, जिमी काटर और रोनाल्ड रीगन ने शिखर पर पहुँचाया, शिखर पर पहुँचने के बाद कैसे और कितनी मात्र में वंचित समूहों की उद्योग-व्यापार, मीडिया इत्यादि में हिस्सेदारी बढ़ी और इस प्रक्रिया में कैसे ब्रायंट हॉवरॉयड, राबर्ट एल. जॉनसन, बिलियम रास्पबेरी, ओप्रा विन्फ्रे, डेंजिल वाशिंगटन, हैलेबेरी, शेला क्रम्प जैसे उद्योगपतियों, पत्रकारों, टी.वी और फिल्मसितारों का उदय हुआ, इसे डॉ. त्रिशरण ने अपनी इस किताब में बखूबी उभारा है। यही नहीं, उन्होंने विश्वनीय स्रोतों से यह सत्य भी उद्घाटित किया है कि डॉ० बी० आर० आंबेडेकर की आरक्षण प्रणाली को अपनाकर अमेरिका ने सर्वव्यापी भागीदारी वाली डाइवर्सिटी नीति को विकसित किया है।

बहरहाल डाइवर्सिटी के गर्भ से निकले अश्वेत उद्योगपतियों, मीडिया व फिल्मकर्मियों

की सफलता से मिशनरी चिंतक डॉ. त्रिशरण इतने अभिभूत हैं कि वे चाहते हैं भारत के दलित-बहुजन समाज की संताने भी राबर्ट एल जॉनसन, रास्पबेरी, बिन्फे, बिल स्मिथ इत्यादि जैसी बनें। चूंकि इन नींगों महानायकों का उदय डाइवर्सिटी के रास्ते ही हुआ है इसीलिए वह डाइवर्सिटी लागू करवाने के लिए जुनून की हद तक वकालत करते नजर आ रहे हैं। इसी जुनून का परिणाम है यह पुस्तक आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं कि इसके पीछे उनकी मंशा मात्र भारत के वंचित समूहों को उद्योगपति, मीडिया स्वामी, थेकेदार, फिल्मकार इत्यादि बनते देखना हैं। उन्हें लगता है डाइवर्सिटी के रास्ते ही भारत में सामंतवाद का ध्वंस, दलित उत्पीड़न में भारी कमी, अस्पृश्यता का खात्मा और सादियों से व्याप्त आर्थिक विषमता का अंत होगा। सर्वोपरि उन्हें लगता है इस प्रक्रिया में हम आने वाले वर्षों में अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों को भी समुद्धि के मामले में पीछे छोड़ जायेंगे।

डाइवर्सिटी में क्रांतिकारी बदलाव की अपार संभावना देख कर ही डॉ. त्रिशरण इस दिशा में कार्यरत बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के पक्ष में लोगों को आहवान करते हुये लिखते हैं- “राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की स्थापना कर लेखक पत्रकार एच.एल.दुसाध ने डाइवर्सिटी प्रचार-प्रसार को पूरे देश में एक जनांदोलन का रूप दे दिया है। इसे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और फ्रांस की क्रांति के तर्ज पर पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। त्याग भावना से ओत-प्रोत होकर इस मिशन को ग्राम स्तर तक ले जाना होगा। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की विभिन्न स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा 'भागीदारी' संबंधी जागरूकता और एडवोकेसी कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य क्रम द्वारा शासन और सरकार का ध्यान इस मिशन की ओर खींचना होगा। यह भारत के मूलनिवासियों के लिए आजादी का आन्दोलन है जिसमें हमें अपना टाइम, टैलेन्ट और मनी का बहुमूल्य योगदान करना होगा। वास्तव में भागीदारी अथवा डाइवर्सिटी साम्यवाद का नवीन सिद्धांत है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने संसार के दुख निवारण हेतु नया धर्म अष्टांगिक मार्ग का आविष्कार किया था, उसी प्रकार भागीदारी दर्शन आज के संदर्भ में आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का एक नया खोज है।“

मेरा मानना है कि डॉ. त्रिशरण ने इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम भागीदारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा काम किया है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इस पुस्तक का महत्व इसीलिए भी रहेगा कि डाइवर्सिटी आन्दोलन मुख्यतः एक बौद्धिक आन्दोलन है जिसमें लेखन का भारी महत्व रहेगा। चन्द्रभान और एच.एल. दुसाध को छोड़ दिया जाय तो वरिष्ठ लेखक बुद्ध शरण और डॉ. विजय कुमार त्रिशरण ही अपने लेखन से इस आन्दोलन को समुद्र कर रहे हैं। जबकि मूलनिवासी समाज के अधिक से अधिक लेखकों को इससे जुड़ना चाहिए था। पर लगता है वे भूमण्डलीकरण के भयावह दौर, जिसमें बहुजनों को अपना वजूद बचाने के लिए

जूझना पड़ेगा, में भावनात्मक मूददों से ही चिपके रहना चाहते हैं। ऐसी निराशाजनक स्थिति में दलितों की आर्थिक मुक्ति पर केन्द्रित इस पुस्तक का आना निश्चित ही एक उल्खनीय घटना है।

दिनांक 26 जुलाई, 2008

इंजि. बृजपाल भारती  
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  
बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, नई दिल्ली

## मनोगत : प्रथम संस्करण

शूद्रों और अतिशूद्रों के लिये भारतीय संविधान में उपबंधित आरक्षण की व्यवस्था उनके लिये सबवर्णों द्वारा चुकाये जाने वाले मात्र ऋण के समान है। मूलधन पर कब्ज़ा तो अभी भी शोषक और सामंत वर्ग का ही है। शूद्र-अतिशूद्र और धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय भारत देश के मूलनिवासी हैं, बहुसंख्यक हैं; फिर भी निर्लजता पूर्वक धोखे से विदेशी आर्य ब्राह्मणों द्वारा लूटे गये हैं। इसी का परिणाम है कि आज दलितबहुजन अपने ही धरती पर गुलाम हैं, कंगाल हैं। परन्तु अब और गुलामी बर्दास्त नहीं करना है। अपनी खोयी हुई धन, धरती और सत्ता को फिर से हासिल करना है। इसके लिये सबसे उत्तम और कारगर उपाय है अपनी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों में भगीदारी सुनिश्चित करना। भगीदारी के इसी सिद्धांत को डाइवर्सिटी कहते हैं। यह जितनाही लाभदायक है उतनाही मुश्किल है इसका कार्यान्वयन। परन्तु यह विल्कुल संभव है। इसके लिये सतत् त्यागपूर्ण जन-आन्दोलन की आवश्यकता है। इसे मुक्ति आन्दोलन का रूप देने की आवश्यता है, तभी हम अतीत के गौरव और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक इसी दिशा में क्रांति की चिनगारी पैदा करने का एक प्रयास है।

मैं बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रकाशक मार्गो एवलो दुसाध साहब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन कर डाइवर्सिटी की अवधारणा को जन-समाज तक सुलभ कराने में महत्व भूमिका निभाया है।

26 जुलाई 2008, आरक्षण दिवस

—डॉ. विजय कुमार त्रिशरण  
आवास संख्या-बी०-६९९  
भवनाथपुर, गढ़वा (झारखण्ड)

## मनोगत : द्वितीय संस्करण

इक्कीसवीं सदी में डाइवर्सिटी के सिद्धांत को बहुजन मुक्ति और उन्नति का एक भीम-औषिधि के रूप में विद्वानों, चिंतकों और प्रगतिशील राजनीतिज्ञों द्वारा पसंद किया जा रहा है। भारत के बहुजन बुद्धिजीवी इस सिद्धांत पर चिंतन करना प्रारम्भ कर चुके हैं। इसका प्रमाण है इस पुस्तक पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से मिले विद्वान पाठकों, लेखकों, राजनीतिज्ञों, राजनीतिक समीक्षकों तथा सामाजिक संगठनों के प्रमुखों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया।

प्रथम संस्करण के साल भर के भीतर ही द्वितीय संस्करण की आवश्यकता पड़ गई, यह इस पुस्तक की लोकप्रियता और आवश्यकता का मिशाल है। डाइवर्सिटी सर्वांगिन विकास का प्रमाणिक सिद्धांत है जिसका ज्वलंत उदाहारण है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का चुना जाना। शोसल डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है। भारत के चतुर्वर्णीय विषमतामूलक समाज में आर्थिक-समाजिक परिवर्तन लाने तथा ओबामा जैसे हुक्मरान पैदा करने के लिये डाइवर्सिटी से और कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता।

इस पुस्तक का उद्देश्य है डाइवर्सिटी के प्रति सभी स्तर के लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा जन-आन्दोलन तैयार कर इसे लागू करनवाने हेतु इसकी प्राप्ती तक संघर्ष करना ताकि भारत की धरती से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद की खात्मा किया जा सके तथा आर्थिक बराबरी पर आधारित बहुजन भारत की स्थापना की जा सके।

मैं दुसाध प्रकाशन के विद्वान प्रकाशक तथा बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं “डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया” मा. एच. एल. दुसाध के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर डाइवर्सिटी आन्दोलन की गति को तीव्रतर किया है।

17 सितम्बर, 2011

—डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

आवास संख्या-बी.-699

भवनाथपुर, गढ़वा (झारखण्ड)

## प्राक्कथन : द्वितीय संस्करण

आज की तारीख में डाइवर्सिटी आंदोलन आंबेडकारी आंदोलन का पर्याय बन चुका है। 1938 में बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने तीव्र इच्छा जताई थी कि दलित आंदोलन दलितों के सामाजिक कष्टों के मुकाबले उनके आर्थिक कष्टों के निवारण पर केन्द्रित हो। बाबा साहेब ने जो वर्षों पूर्व चाहा था, वह 21वीं सदी में भूमंडलीकरण के विस्तार के साथ-साथ आगे बढ़ रहा है। इसका प्रमुख श्रेय डाइवर्सिटी आंदोलन को जा रहा है। यह आंदोलन अभी जनांदोलन का रूप नहीं लिया है, लेने की प्रक्रिया में। यह मुख्यतः लेखन के रूप में है।

इस वैचारिक आंदोलन के फलस्वरूप दलित समाज में सरकारी नौकरियों से आगे निकल कर सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, फिल्म, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों इत्यादि में भी संख्यानुपात में हिस्सेदारी चाहत पैदा हो रही है। सरकारें भी उनकी चाहत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें उद्योग-व्यापार में भागीदार बनाने की योजना पर काम करने लगी हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 25 जून, 2009 को सभी प्रकार के सरकारी ठेकों में एससी/एसटी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया। इसका असर केन्द्र की संप्रग सरकार पर भी पड़ा है। संप्रग सरकार एससी/एसटी को सरकारी खरीद में आरक्षण देने की कार्य योजना पर आगे बढ़ रही है। भाजपा भी लोकसभा चुनाव-2009 के अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर डाइवर्सिटी लागू करने की बात कह चुकी। असर दूसरी राज्य सरकारों पर भी हो रहा है।

डाइवर्सिटी आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने में एच.एल.दुसाध, चन्द्रभान प्रसाद, बुद्ध शरण हंस, दिलीप मंडल के साथ ही डॉ. विजय कुमार त्रिशरण ने ऐतिहासिक कार्य किया है। वे न सिर्फ वर्षों से इस पर लगातार कलम चला रहे हैं बल्कि फिल्ड में उत्तरकर जन-जागरण भी चला रहे हैं। बतौर लेखक वह आम लोगों को अपनी सहज लेखनी से डाइवर्सिटी की उपयोगिता समझाने में महारत हासिल कर चुके हैं। इस दिशा में 2009 में प्रकाशित 'आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी' उनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसकी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने उसका यह दूसरा

खण्ड तैयार किया है। इसमें भी उन्होंने पहले पार्ट के स्तर को बनाये रखा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तक भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल होगी। मैं डॉ. त्रिशरण की दीर्घायु की कामना करता हूँ तथा डाइवर्सिटी पर एक और मारक रचना देने के लिए बधाई देता हूँ।

—डॉ. कौलेश्वर  
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र

## अनुक्रम

खण्ड - 1

### आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी

|  |    |
|--|----|
| भारत की सामाजिक व्यवस्था .....                 | 17 |
| सामाजिक सुधार की प्रक्रिया .....               | 19 |
| आरक्षण बनाम डाइवर्सिटी .....                   | 23 |
| सिर्फ आरक्षण से मुक्ति संभव नहीं .....         | 29 |
| मुस्लिम समस्या का सही उपचार : डाइवर्सिटी ..... | 32 |
| डाइवर्सिटी की प्रयोगशाला : अमेरिका .....       | 34 |
| विकसित भारत डाइवर्सिटी से ही संभव .....        | 38 |
| डाइवर्सिटी की अवधारणा शुद्ध भारतीय .....       | 39 |
| डाइवर्सिटी मूवमेंट और इसका प्रभाव .....        | 42 |
| सर्वण विवेक और डाइवर्सिटी .....                | 45 |

खण्ड - 2

### डाइवर्सिटी के विभिन्न रूप

|  |    |
|--|----|
| दलितोत्थान में विज्ञापन और एन.जी.ओ. डाइवर्सिटी की भूमिका ..... | 53 |
| डाइवर्सिटी-आर्थिक मुक्ति का अचूक अस्त्र .....                  | 56 |
| सामंती दमन का जबाव है : डाइवर्सिटी .....                       | 60 |
| अस्पृश्यता की उत्पति आर्थिक गैर-बराबरी के गर्भ से .....        | 62 |
| डाइवर्सिटी आन्दोलन के लिये संगठित प्रयास की जरूरत .....        | 65 |
| मिशन डाइवर्सिटी गीत .....                                      | 69 |
| डाइवर्सिटी से आजादी .....                                      | 71 |
| डाइवर्सिटी सुकृति-कण .....                                     | 72 |



---

ਖਣਡ - 1

ਆਰਕਾਣ ਬਨਾਮ ਡਾਇਵਰਿੰਟੀ

---



## भारत की सामाजिक व्यवस्था

भारतीय समाज चतुर्वर्णीय विधान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। इसमें चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऐसी समाज संरचना को वर्ण-व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण-व्यवस्था हिन्दू धर्म की आधारशिला है जो हिन्दू धर्म में असमानता का मूल कारण है। वास्तव में वर्ण-व्यवस्था एक प्रकार की हिन्दू आरक्षण-व्यवस्था है, जिसमें पढ़ना, पढ़ना, यज्ञ और धार्मिक-संस्कार करना ब्राह्मणों का काम है; युद्ध करना क्षत्रियों का तथा खेती-व्यापार करना वैश्य के लिये विहित है। शूद्रों का काम इन तीनों वर्णों को बिना मजदूरी लिये निःस्वार्थ भाव से गुणगान करते हुये सेवा करना निर्धारित है। वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत चारों वर्णों के पेशों को परिवर्तनशीलता से मुक्त रखा गया अर्थात् कोई भी वर्ण एक दूसरे के पेशा को नहीं अपना सकता था; हर वर्ण केवल अपना विहित पेशा ही अपना सकता था। वह मृत्यु पर्यन्त उसी वर्ण के कर्म करने के लिये बाध्य था जिसमें उसका जन्म हुआ है। इसे लागू करने के लिये कड़े नियम बनाए गए। इस कानून का उल्लंघन करने वाला विधर्मी कहा जाता था तथा कठोर दंड का अधिकारी होता था। वर्ण-व्यवस्था की इसी अपरिवर्तनशीलता के कारण भारत हजारों सालों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा।

वर्ण-व्यवस्था श्रेणीबद्ध असमानता (Graded inequality) के सिद्धांत पर आधारित समाज-व्यवस्था है। श्रेणीबद्ध असमानता का अर्थ होता है चारों वर्णों का एक दूसरे से श्रेष्ठता-निकृष्टता के आधार पर विभाजन। इसमें विभाजन का क्रम ब्राह्मण से शूद्र हो कर शूद्र वर्ण पर खत्म होता है। चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) को उर्ध्व स्थिति (ऊपर से नीचे) में रखा गया है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र का स्थान रखा गया है। वर्णव्यवस्था को उल्टे क्रम में लागू नहीं किया जा सकता है अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तो ब्राह्मण गुलाम बना सकता है परन्तु ब्राह्मण इन तीनों वर्णों का गुलाम नहीं बन सकता। एक वैश्य किसी वैश्य, शूद्र तथा अतिशूद्र को गुलाम बना सकता है, परन्तु ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय को नहीं। एक अतिशूद्र किसी अतिशूद्र को ही गुलाम बना सकता है, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को नहीं।'

शूद्रों को न केवल समाज-विभाजन के सबसे नीचले स्तर पर रखा गया है बल्कि उन पर अनगिनत कलंक और निर्योग्यताएँ लाद दी गई हैं ताकि उन्हें कठोर नियमों द्वारा बांध कर उनकी तरक्की को रोका जाय। मनुस्मृति का विधान था कि:-

1. न शूद्राय मतिं दद्यात्—शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। मनु-4-80
2. शव्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनं संचयः—सक्षम होने पर भी शूद्र धन का संचय न करें। मनु-10-129
3. वंसासि मृतं चेतानि—शूद्र मूर्दों पर का उतरन पहनें। मनु-10-52
4. भिन्नं भाण्डेषु भोजनम्—शूद्र टूटे-फूटे वर्तन में भोजन करें। मनु-10-52
5. उच्छिष्टमन्नं दातण्यं—शूद्र जूठा भोजन करे। मनु-11-125
6. कार्णाय सम अलंकारः—शूद्र महिलाएँ लोहे का गहना पहनें। मनु-10-52
7. परिग्रन्ध्या च नित्यशः—वह एक स्थान पर स्थिर न रहे, हमेश घुमता-फिरता रहे। मनु-10-52
8. चण्डालं च श्वपचानां वर्हिग्रामात् प्रतिश्रय—अछूत गाँव के बाहर बसें। मनु-10-51

मनु के उपर्युक्त विधान के कारण शूद्रातिशूद्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग) पशुवत जीवन जीने को मजबूर हो गये। इतना ही नहीं, इन निर्योग्यताओं को कानूनी और दंड-विषयक प्रावधान से जोड़ा गया ताकि उस व्यक्ति को दंडित किया जा सके जो इस नियम की अवहेलना करता है; यथा—

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।

तं राजा निधनं कल्या क्षिप्रमेव प्रवासयेत्॥ मनु-10-96

“अर्थात् जो अधम जाति (शूद्रातिशूद्र वर्गी) लोभवश उत्तम आजीविका से जीवन निर्वाह करता हो उसको राजा निर्धन करके शीघ्र ही देश से निकाल दे।” निर्योग्यताओं के उल्लंघन के विरुद्ध मनु का यह दंड-विधान मूलनिवासी दलित-बहुजन समाज को घोर आर्थिक विपन्नता और चरम दरिद्रता की स्थिति में ला पटका। यहीं से अस्पृश्यता की शुरुवात होती है। वर्तमान आर्थिक गैर-बराबरी का मूल मनुविधान ही है।

इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था और इसका श्रेणीबद्ध असमान विभाजन भारत को बड़ा अहित किया; सर्वशक्तिमान और साधन सम्पन्नता के बावजूद भारत हजारों साल तक गुलाम रहा क्योंकि हिन्दुओं में कभी अपनत्व, सौहार्द और संगठन भावना नहीं रही। आर्थिक गैरबराबरी के इतिहास की शूलआत वर्णव्यवस्था के सिद्धांत से होती है। वर्ण-व्यवस्था वास्तव में ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी श्रेष्ठ चीजों के उपभोग का विशेषाधिकार ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। बहुजन हमेशा ही विपन्न, वित्त-रहित और दीन-हीन दशा में रहने को विवश हुए जिसका असर आज भी देखा जा सकता है।

## सामाजिक सुधार की प्रक्रिया

भारत में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया भगवान बुद्ध से शुरू होती है। तथागत बुद्ध विश्व के प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी मान्यताओं की जड़ें हिला कर रख दीं। उन्होंने मावनतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा कृषकों (आम प्रजा) के पक्ष में पशुबलि के विरुद्ध व्यापक जन-आन्दोलन चलाया। यज्ञों में बड़े पैमाने पर गो-बलि दिये जाने की धार्मिक नियमों के कारण कृषि के लिये बैलों की कमी हो जाती थी। इससे खेती-बागी बाधित होने के कारण अनाजों की उपज प्रभावित होती थी। यह कृषकों के लिये भारी आर्थिक नुकसान का मामला था। भगवान बुद्ध ही वे प्रथम महामानव थे जिन्होंने अहिंसा को जीवन के आदर्श के रूप में अपनाने का आह्वान किया तथा आम जन में गाय के प्रति आदर का भाव पैदा कर ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में होने वाले गो-बघ पर विराम लगा दिया। बुद्ध की इस क्रांति का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

बुद्ध के उपदेश में आर्थिक-दर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। एक प्रश्न के उत्तर में खुदक पाठ नामक ग्रंथ में बुद्ध ने कहा है कि सभी प्राणि भोजन पर आधारित हैं “सबे सत्ता आहारटिठका”। धम्मपद में बुद्ध ने भूख को सबसे बड़ा रोग बताया है-“जिधिच्छा परमारोगा”। इस रोग को मिटाने के लिये भोजन ही एकमात्र औषिधि है और भोजन की पूर्ति के लिये खाद्यान्न ही माध्यम है। यही कारण है कि बुद्ध ने खाद्यान्न को सबसे बड़ा धन बताया है “नथिधान्य समं धनं”। इस खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिये कृषिकार्य आवश्यक है। कृषिकार्य के लिये बैलों की आवश्यकता पड़ती है जो गाय से प्राप्त होता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने भारत में प्रथम बार गाय के महत्व को प्रतिष्ठापित किया और उसकी रक्षा के लिये सिद्धांत बनाए।

बुद्ध ने शील और समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। बहुजन हित और सुख के लिये भिक्खु संघ की स्थापना की जिसका द्वार ब्राह्मण-चंडाल सभी के लिये खुला था। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने सामाजिक सुधार और क्रांति की प्रथम शुरुवात की।

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कबीर और गुरु रविदास ने सामाजिक क्रांति का भीमनाद किया। गुरु रविदास ने “बेगमपूरा शहर” की परिकल्पना कर तत्कालिन समाज में सामाजिक-आर्थिक आधार पर समानता की जरूरत को समझाया। वंचित लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिये उपर्युक्त किया। कोई भी समाज बेगम अर्थात् दुःख-रहित तभी हो सकता है जब उस समाज में आर्थिक समानता और सम्पन्नता हो। ब्राह्मण-बहुजन में मानवीय आधार पर फर्क न हो।

भारत के मूलनिवासी दलित-बहुजनों की दयनीय दशा में सुधार के लिये आरक्षण

# Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

## Join Our Inclusive Reading Community

- ✓ We champion diverse voices and perspectives
- ✓ Your support helps amplify underrepresented authors
- ✓ We provide free access to educational institutions
- ✓ Building bridges through shared stories
- ✓ Creating space for all narratives to be heard

## Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

**Visit: [www.diversitymission.in](http://www.diversitymission.in)**

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library